ment generated at the district and village levels are maintained at the Government of India level.

To give adequate coverage to women under employment generation, 30 per cent employment opportunities under JRY have been earmarked for women. However, to some extent, due to social taboos or preference of a family to send male member for manual work, the required number of women workers do not report for JRY works in some States.

नई पंचायती राज प्रणाली के अधीन चुनाव

7091. **श्री रामजी लाल :**
श्री येरा नारायणा स्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के लिये संविधान संशोधन विधेयक के अधिनियम के बाद छः माह की अवधि के भीतर पंचायती राज निकायों के चुनाव कराना अनिवार्य है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को अपने-अपने राज्य के पंचायत निर्वाचन आयोग के माध्यम से नयी पंचायत प्रणाली (त्रि-स्तरीय) के लिये सभी राज्यों में चुनाव कराने की सलाह दी है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में नयी पंचायत प्रणाली स्थापित कर दी गई है ;

(घ) किन-किन राज्यों में यह प्रणाली अब तक स्थापित नहीं की गई है ;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1994-95 के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ; और

(छ) पंचायत चुनाव कराने के लिये हरियाणा राज्य को वर्ष 1994-95 के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पंचायती राज के संबंध में राज्य कानन बनाये जाने के पश्चात् धारा 243 बी (1), 243ई (3) तथा 243(4) के साथ पठित राज्य अधिनियम में इस आशय हेतु किये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवा सकते हैं ।

(ख) भारत सरकार ने सभी राज्यों को सूचित किया है कि पंचायती राज कानूनों में परिवर्तन करने के पश्चात राज्यों को जहां कहीं चुनाव कराये जाने अपेक्षित हैं, वहां पर चुनाव कराने होंगे ।

(ग) से (ङ) सभी राज्यों ने अपने राज्य अधिनियमों को संविधान (173वां) संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुरुप बनाने के लिये कानन बना लिये हैं, जिसके पश्चात् राज्यों द्वारा तदनुसार आगे कदम उठाये जायेंगे ।

(च) और (छ) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । इस प्रयोजन हेतु राज्यों को निधियां स्वीकृत करने के लिये भारत सरकार की कोई योजना नहीं है ।

JRY Grants in Andhra Pradesh

7092. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government reduced J.R.Y. grants to Andhra Pradesh;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether the Andhra Pradesh Government has directed the J.R.Y. fund, to other purposes;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL